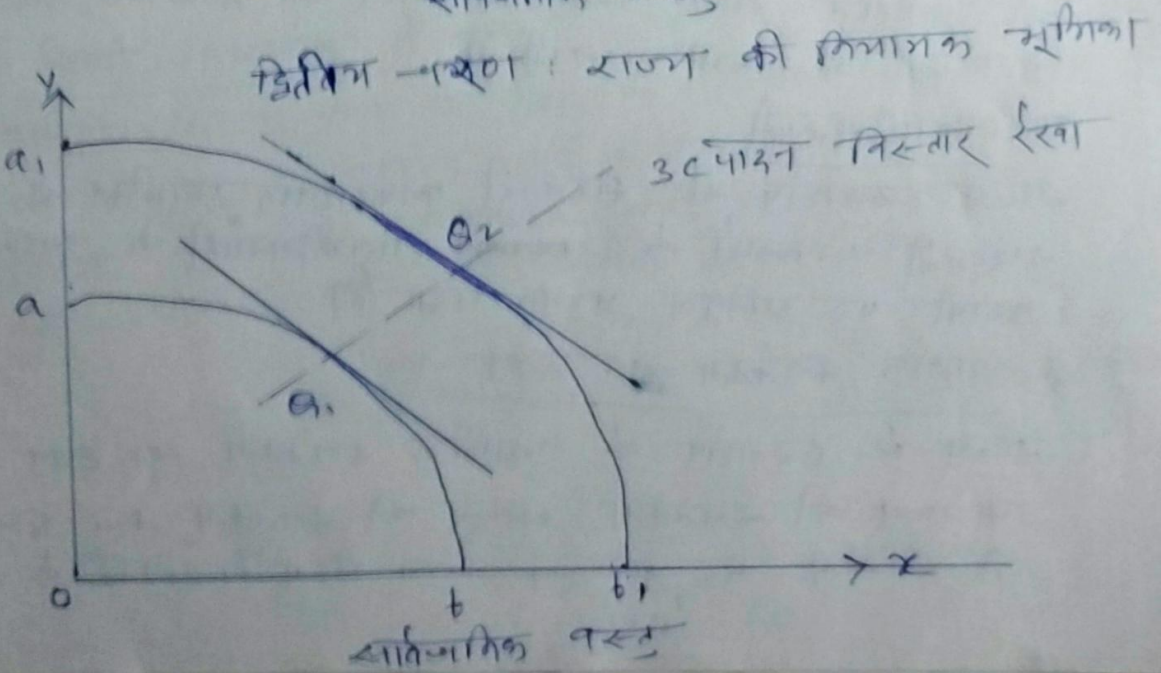
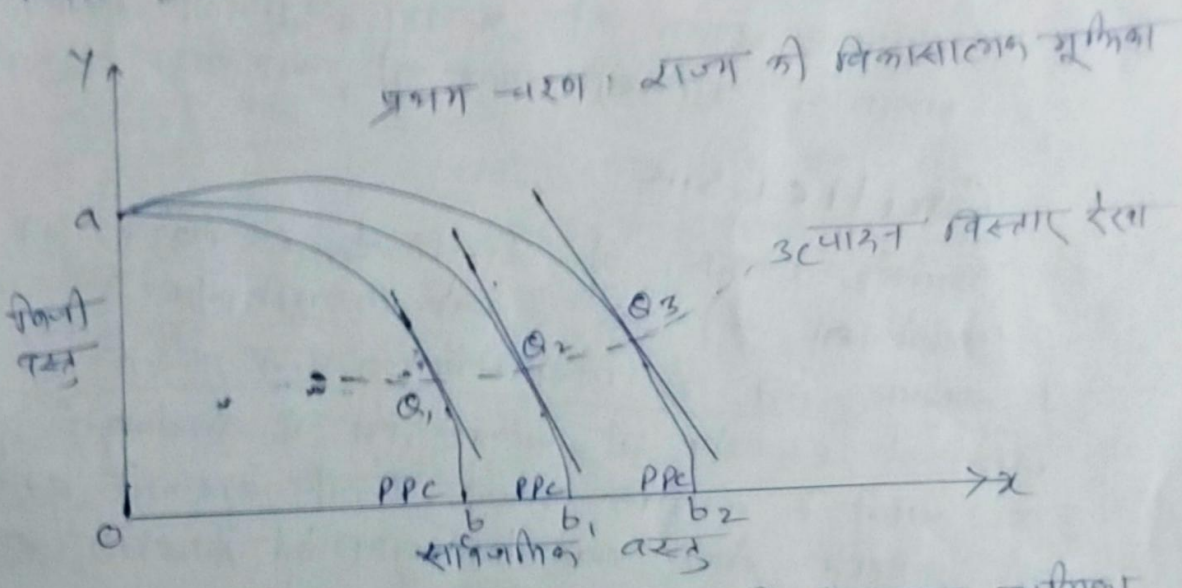


(i) प्रगतिशील मजदूरी लागू कर कृषि के विकास को विषमता को दायज दूर करती है।

(ii) मुद्रास्फीति के कारण मंहगी लागू मीते तथा अक्सर मा मंदी के कारण सरकारी खास मीते के कारण भारी ऋणों में लागू करती है। कृषि क्षेत्रों से न मिलेवाकती प्रभावित करने जाते हैं।

इस प्रकार राज की विकास लागू श्रमिकों को प्रभाव चरण को कार्य रूप मिलाकर श्रमिकों को द्वितीय चरण को कार्य कर कहा जाता है जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं -



उपयुक्त निम्न में प्रथम चरण में आर्थिक विकास
गति तीव्र करने के लिए सरकार स्वयं विकासवादी
परिभाषणाओं पर आत्मनिर्भरता का काम करेगी ताकि
आर्थिक संरचना में सुदृढ़ हो जाय।

उसी प्रकार द्वितीय चरण में राज्य कृषि
श्रमिका के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन
सुदृढ़ कराने में सफल होगी। इसके फलस्वरूप आर्थिक
विकास त्वरित होगा।

इस प्रकार आर्थिक विकास में राज्य की
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। विकासवादी
भूमिका राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका होती है जबकि
विकासवादी भूमिका राज्य की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है।

Criticism

आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप की कड़ी
आलोचना की गई है जो निम्नलिखित है -

1. बाजार तंत्र में विसंगतियों उत्पन्न करना

राज्य के हस्तक्षेप से बाजार तंत्र में विसंगतियाँ उत्पन्न
हो जाती हैं क्योंकि निजी उद्योगी सरकारी हस्तक्षेप
से आहत होकर निरिच्छा हो जाते हैं। इससे राष्ट्रीय
उत्पादन में कमी आती है।

2. लालफीताशाही

राज्य हस्तक्षेप से सरकारी अफसरवाद स्थापित हो जाता है
सरकारी अफसरों के ~~काम~~ लालफीताशाही के कारण निजी
उद्योगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता का हान

राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक स्वतंत्रता का हान होता है।
उद्योगी की स्वतंत्रता, बाजार की स्वतंत्रता तथा उत्पादक
की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्पादकों के प्राथमिक

की गतिशीलता में व्यापक उत्पन्न होता है।

4. स्वचालित गुल्म क्षेत्र की खोज

राज्य के हस्तक्षेप से बाजार क्षेत्र के द्वारा मुक्त परिवर्तन को संकेत से निर्देशन मिली खोजी को नहीं मिल पाता है। उत्पादन को निर्णय सरकारी निर्णय बन जाता है जो कि बेलायत के गुण से प्रेरित है।

5. प्रेरणा का अभाव

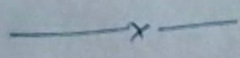
राज्य के हस्तक्षेप से ही ~~बाजार क्षेत्र के विकास~~ आर्थिक व्यवस्था में लागू प्रवृत्ति स्वी प्रेरणा का अभाव हो जाता है। सभी आर्थिक क्रियाएँ सरकारी आदेश का इंतजार करती हैं।

6. गुलाबी का मार्ग "Road to Serfdom"

Prof Hayek के अनुसार राज्य की सारी क्रियाएँ निर्णयन के माध्यम होती हैं निर्णयन या योजनाकरण अर्थव्यवस्था को गुलाबी के मार्ग पर ले जाती है। योजना आयोग ही सभी निर्णय लेगा कि देश में कितना उत्पादन होगा और कैसे वितरण होगा। इसलिए योजना गुलाबी का मार्ग है जिले राज्य हस्तक्षेप से लागू किया जाता है।

7. मिजी विनिर्माण में व्यापक

राष्ट्रीयकरण के नाम से देश के पूंजीपति अपनी पूंजी को देश में लगाना पसन्द नहीं करते। इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी भी हतोत्साहित होती है। ऊल्लसव्य औद्योगिकीकरण की गति धीमी रहती है।



Dr Sandhya Rani
Maharaja College